खंड . 2 अंक . 7 फरवरी 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन क्षेत्र में देश के एक प्रमुख तकनीकी संगठन के रूप में विकसित हुआ है और अब आयोग अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में है. 75वें वर्ष के उत्सव के तौर पर और बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर-संरचनात्मक उपायों के महत्व को देखते हुए 17.01.2020 को अपर गंगा बेसिन संगठन, के.ज.आ. द्वारा लखनऊ में "फ्लड प्लेन ज़ोनिंग" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

फ्लड प्लेन ज़ोनिंग का उद्देश्य अलग-अलग परिमाणों या आवृत्ति वाले बाढ़ से प्रभावित जोन या क्षेत्रों का सीमांकन करना है और इन क्षेत्रों में मुनासिब विकास के प्रकारों को निर्धारित करना है, ताकि बाढ़ के कारण जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. इस कार्यशाला का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया और इसमें विभिन्न संगठनों जैसे कि सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के प्रतिभागियों ने भाग लिया.

फरक्का बैराज के कारण बिहार राज्य में गंगा नदी में गाद और बाढ़ पर काफी चर्चा हुई है. इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जोकि अध्ययन के लिए टीओआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है.

हमारा देश विगत में जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए राज्यों के बीच बेहतरीन सहयोग का साक्षी रहा है. हालांकि, जनसंख्या में वृद्धि और पानी की बढ़ती मांग के कारण, गुजरते समय के साथ-साथ राज्यों के बीच सीमित संसाधन विवाद का कारण बन गया है. सुप्रसिद्ध नौ अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों के अलावा, हाल ही में तिलैया धाधर विपथन योजना (बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच) और पेंनीयार नदी और उसकी सहायक नदियों (तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच) पर भी विवाद शुरू हो गए हैं. भारत सरकार द्वारा आईएसडब्लूआरडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोनों विवादों के समयबद्ध समाधान के लिए मेरी अध्यक्षता में समझौता वार्ता समितियों की स्थापना की गई है. समझौता वार्ता समितियां ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच हैं जो विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर सकती हैं जिससे लंबे समय तक चलने वाली अधिनिर्णयन प्रक्रिया से बचा जा सके. ये दोनों समितियां मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं.

केन्द्रीय जल आयोग को शुरू में 5 अप्रैल 1945 को केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग (सीडब्ल्यूआईएनसी) के रूप में स्थापित किया गया था. यह आयोग 5 अप्रैल 2020 तक अपनी मौजूदगी के 75 साल पूर्ण कर लेगा. के.ज.आ. भारत और साथ ही पड़ोसी देशों में जल संसाधनों और जल-विद्युत के विकास में किए गए अपने योगदान पर एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन करके इस अवसर का उत्सव मनाएगा.

इस नए साल में, पचास से अधिक केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को उनके अगले पदक्रम में पदोन्नत किया गया. उन सभी को उनके भावी दायित्वों के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं .

आर.के.

विषय-वस्तु

- जम्मू व कश्मीर में माननीय जल शक्ति मंत्री का दौरा
- फ्लड प्लेन ज़ोनिंग पर कार्यशाला का उद्घाटन
- नेपाल में अरुण- III जल विद्युत परियोजना
- सिंचाई प्रणालियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पर संचालन समिति की तीसरी बैठक
- भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी
- माजुली के लिए टीएसी की बैठक
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
- ऐक्वेटिक हैबिटेट एटलस
- इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का ईआईए अध्ययन
- तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)
- कोपिली जल विद्युत परियोजना का दौरा
- राजस्थान में चंबल बेसिन बांधों के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों का दौरा
- नॉर्थ कोयल परियोजना की समीक्षा
- त्रिपुरा की परियोजनाओं का पीएफआर
- बाढ़ प्रबंधन पर हिंदी तकनीकी संगोष्ठी
- डीआरआईपी
- सिंचाई प्रणाली की बेंचमार्किंग पर कोर ग्रुप की 10 वीं बैठक
- बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह
- जलाशय प्रबोधन
- स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति
- इतिहास - भाखड़ा बांध

जम्मू व कश्मीर में माननीय जल शक्ति मंत्री का दौरा

माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 21 से 22 जनवरी, 2020 के दौरान जम्मू और पठानकोट का दौरा किया. माननीय मंत्री जी के साथ ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और के.ज.आ. के अधिकारी भी थे.

समीक्षा बैठक के तुरंत बाद, माननीय मंत्री पंजाब में शाहपुरकंडी बांध स्थल के लिए रवाना हुए. रास्ते में माननीय मंत्री ने रणजीत सागर बांध का हवाई सर्वेक्षण किया और शाहपुरकंडी बांध स्थल पर पहुँचे जहाँ उन्हें परियोजना की अब तक प्राप्त प्रगति के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें परियोजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया, जो 206 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और जम्मू व कश्मीर में 32000 हेक्टेयर और पंजाब में 5000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा.

तत्पश्चात, माननीय मंत्री ने उझ बहुउद्देशीय परियोजना के बांध और बैराज के प्रस्तावित स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और मौजूदा उझ बैराज स्थल पर पहुंचे . परियोजना स्थल पर उन्हें परियोजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया, जो 196 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र की 16743 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा, जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. माननीय मंत्री ने परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए जोर दिया.

उझ परियोजना स्थल पर माननीय मंत्री जी

अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा फ्लड प्लेन ज़ोनिंग पर कार्यशाला का उद्घाटन

वर्ष 1945 से के.ज.आ. जल संसाधन के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख तकनीकी संगठन के रूप में विकसित हुआ है और अब 75वें वर्ष में उसी का समारोह मनाने और गैर-संरचनात्मक उपायों के महत्व पर विचार करते हुए अपर गंगा बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग द्वारा "फ्लड प्लेन ज़ोनिंग" विषय पर एक कार्यशाला 17.01.2020 को लखनऊ में आयोजित की गई.

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किया गया. कार्यशाला में एनआईएच, रुड़की के निदेशक डॉ एस.के. जैन और श्री ए.के. श्रीवास्तव, इंजीनियर-इन-चीफ एवं विभागाध्यक्ष, यूपीआईएंड डब्ल्यूआरडी, लखनऊ ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया. श्री भोपाल सिंह, मुख्य अभियंता, के.ज.आ., लखनऊ और श्री रवींद्र सिंह, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग ने उद्घाटन सत्र में अतिथियों के साथ मंच को साझा किया. केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / संगठनों (नामतः ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., सीजीडबल्यूबी, एनआईएच, एनएमसीजी, एनडीएमए, कृषि, आदि), उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड राज्य सरकारों (नामतः सिंचाई विभाग, एसडीएमए, सीएडीए, डब्लूएएलएमआई, आदि), उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम- यूपीपीसीएल, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान (नामतः बीबीएयू, आरएमएसआई, आईआईटी बीएचयू) के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया. श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने गैर-संरचनात्मक उपायों के महत्व और इसके लाभों पर चर्चा की तथा राज्य सरकारों द्वारा जमीनी स्तर पर इसे लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. अन्य सदस्यों के साथ फ्लड प्लेन ज़ोनिंग पर कार्यशाला में भाग लेते हुए

फ्लड प्लेन ज़ोनिंग एक गैर-संरचनात्मक उपाय है जिसका उद्देश्य अलग-अलग परिमाण या आवृत्तियों और संभावना स्तरों पर बाढ़ द्वारा प्रभावित ज़ोन या क्षेत्रों को सीमांकित करना है तथा इन क्षेत्रों में मुनासिब विकास के प्रकारों को निर्धारित करना है ताकि जब भी वास्तव में बाढ़ आए, तो नुकसान कम से कम हो अगर उसे रोका न जा सके. इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों (111 पंजीकृत प्रतिभागियों) ने भाग लिया.

अध्यक्ष के नेतृत्व में के.ज.आ. की टीम द्वारा अरुण-III एचईपी (900 मेगावाट), नेपाल का दौरा

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के नेतृत्व में के.ज.आ. के डिजाइनरों की एक टीम जिसमें श्री एस.के. सिब्बल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू), श्री अनिल जैन, निदेशक, सीएमडीडी (एनएंडडब्ल्यू), श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एनएंडडब्ल्यू) और श्री मनोज मीणा, उप निदेशक शामिल थे, ने अरुण-III हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (900 मेगावाट), नेपाल का 19.01.2020 से 23.01.2020 के दौरान दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इस टीम द्वारा दौरे के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के डिजाइनरों, परियोजना के इंजीनियरों के साथ दाहिने किनारे के स्लोप स्टेबिलिटी उपायों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई.

इस परियोजना को एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और के.ज.आ. एक प्रतिधारक सलाहकार के रूप में डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान कर रहा है. निर्माण कार्य परियोजना के लगभग सभी घटकों पर चल रहा है नामतः बांध की धुरी पर उत्खनन, डायवर्जन टनल का निर्माण, सर्ज शाफ्ट और बिजलीघर परिसर. एचआरटी का निर्माण 5 विभिन्न चरणों में जारी है. 900 मेगावाट पावर की क्षमता वाले अरुण-III हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण नेपाल में एसजेवीएनएल द्वारा बीओटी आधार पर किया जा रहा है. इस आरओआर परियोजना में 70 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है और 11.78 किमी लंबाई के 9.5 मीटर व्यास वाले एचआरटी के जरिए पानी को पहुंचाया जाएगा. इस परियोजना में 225 मेगावाट की 4 टरबाइनों के लिए एक भूमिगत पावर हाउस परिसर और ओपेन स्काई सर्ज टैंक बनाने की परिकल्पना की गई है.

वर्ष 2017-18 में 4 अलग-अलग पैकेजों में कार्य सौंपे गए. दो पैकेज सिविल कार्यों के लिए, एक हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए और एक इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए है. कार्य पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2023 है. वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि जुलाई 2023 निर्धारित है.

रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके सिंचाई प्रणालियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पर संचालन समिति की तीसरी बैठक

सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर सिंचाई प्रणालियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पर संचालन समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 15.01.2020 को आयोजित की गई. इस बैठक में विश्व बैंक के अधिकारियों ने भारत में 10 चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग गाइडेड प्रदर्शन मापन प्रणाली का मसौदा प्रस्तुत किया.

विश्व बैंक की टीम से श्रीमती मारिया ने समिति को सूचित किया कि सभी 10 परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक अध्ययन के.ज.आ. से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है और यह अध्ययन प्रमुख योजनाओं के सिंचाई कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए एक निर्देशित मापन तंत्र है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस अध्ययन में रिमोट सेंसिंग का उपयोग परियोजना के परिणाम को देखने हेतु किया गया है, जो सिंचाई के पानी तक पहुंच है. उन्होंने नतीजों के लिए संकेतकों जैसे कि न्यायसंगत पहुंच, उत्पादक उपयोग और स्थिर जल-संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के एक संग्रह पर चर्चा की. विश्व बैंक की टीम के श्री मुत्लु ने अध्ययन प्रस्तुत किया और बताया कि उन्होंने रिमोट सेंसिंग (ईटी के स्थानिक मानचित्र) से वास्तविक वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन (ईटीए) की भिन्नता के गुणांक (सीवी) की अवधारणा का उपयोग किया है, ताकि किसी योजना में पानी के प्रयोग की समरूपता और विषमता का पता चल सके .

उन्होंने परिणामों के बारे में 10 संकेतकों जैसे लाभदायक पानी के लिए न्यायसंगत और लागत प्रभावी पहुंच, पानी की उत्पादकता, उपयोग और स्थिर जल विज्ञान पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर चर्चा की. उन्होंने ऊपरी बारी दोआब नहर, पंजाब और बोरादिकारई, असम की सिंचाई कमान का उदाहरण देते हुए थ्रेशहोल्ड या बेंचमार्क के रूप में 10% की भिन्नता का गुणांक लेते हुए सिंचाई कमान में रबी के मौसम के दौरान एक समान पानी की खपत से मापे गए वितरण संकेतक की न्यायसंगतता के बारे में भी चर्चा की .

भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी

भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्लूपी) मार्च 2016 में आयोजित 13वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का परिणाम है. भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी के तहत भारत यूरोपीय संघ के तकनीकी सहकार्यता के लिए विभिन्न गतिविधियों की पहचान की गई थी.

भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी के प्राथमिकता क्षेत्र -2 के तहत, एक संयुक्त कार्यदल जिसमें केंद्रीय जल आयोग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, आईईडब्लूपी / जीआईजेड पीएमयू के प्रतिनिधि व यूरोपीय संघ इको-हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं, भारत में तीन नदी घाटियों के पर्यावरण प्रवाह के मूल्यांकन के लिए काम कर रहा है. इसमें कीस्टोन प्रजातियों के लिए प्रवाह और जलीय आवास परिस्थितियों के बीच संबंधों को समझने के लिए विस्तृत इको-हाइड्रोलॉजिकल और इको-हाइड्रोलिक गतिशीलता के आधार पर मजबूत तरीकों का प्रारंभिक परीक्षण शामिल है. इसके लिए, संयुक्त टीम द्वारा पारिस्थितिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजिकल और रूपात्मक स्थितियों आदि से संबंधित क्षेत्र का प्रेक्षण किया जा रहा है.

02 से 05 जनवरी 2020 के दौरान, संयुक्त टीम ने रामगंगा नदी बेसिन के क्षेत्र का दौरा किया. नदी के क्रॉस सेक्शन, प्रवाह की गहराई और प्रवाह वेग आदि को नाव पर लगाए गए एडीसीपी से और मैनुअल अवलोकन (उथले गहराई पर) का भी उपयोग करके एकत्र किया गया. जलीय जीवों की प्रजातियों (मछली और सूक्ष्म-अकशेरुकी) और प्लवक आदि के नमूने मैनुअल तरीकों (कास्ट-नेट और प्लेंक्टन नेट आदि) का उपयोग करके एकत्र किए गए. ड्रोन आधारित फोटोग्राममेट्री तकनीक का उपयोग करके अध्ययन स्थल के उच्च रिज़ॉल्यूशन हवाई चित्र प्राप्त किए गए हैं, ताकि पूल, ग्लाइड, रन आदि जैसे स्ट्रीम फीचर्स के कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस को समझा जा सके. बेसिन में महत्वपूर्ण प्रतिनिधिक स्थलों पर सब्सट्रेट की स्थिति देखी गई. ये व्यापक पर्यवेक्षण विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियों के अनुरूप पर्यावरणीय प्रवाह परिदृश्यों का आकलन करने के लिए बेसिन हेतु हैबिटट मॉडलिंग अध्ययन में जानकारी जोड़ेंगे.

रामगंगा नदी बेसिन के क्षेत्र में दौरे के दौरान भारत यूरोपीय संघ का संयुक्त कार्यदल

माजुली के लिए टीएसी की बैठक

"ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" योजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-बीबी) का 10वां दौरा 4 से 5 जनवरी, 2020 के दौरान किया गया. सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-बीबी) ने अन्य अधिकारियों नामतः मुख्य अभियंता(एफएम), के.ज.आ., आयुक्त(बीएंडबी), ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राज्य सरकार के अधिकारियों, आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर आदि के साथ "ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव और बाढ़ से माजुली द्वीप का संरक्षण" स्कीम के अंतर्गत बाढ़ और कटाव से संबंधित हाल की उभरती हुई चुनौतियों से बचाव के उपायों के लिए 04.01.2020 को सलमाड़ा से बासमारा तक दौरा किया.

तकनीकी सलाहकार समिति का माजुली द्वीप दौरा

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत कावेरी, नर्मदा और यमुना बेसिन में बेसिन-वार विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान (बहुसप्ताहिक पूर्वानुमान) की परामर्श सेवाओं के लिए केंद्रीय जल आयोग के सदस्य(आरएम) की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति की तकनीकी वार्ता की बैठक 17 जनवरी 2020 को हुई . राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) की खरीद के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा आमंत्रित निविदा की तकनीकी बोली क्रमशः 24.01.2020 और 27.01.2020 को खोली गई. पूर्वोतर राज्यों के आरटीडीएएस निविदा के संबंध में चार बोलीदाताओं और नर्मदा आरटीडीएएस के संबंध में पाँच बोलीदाताओं से तकनीकी बोली प्राप्त हुई और इन बोलियों की तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है. के.ज.आ. द्वारा आमंत्रित सात नदी घाटियों रामगंगा, बराक, नर्मदा, कावेरी और पश्चिमी घाट में तीन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों कुट्टीदीपुझा, पीची एवं मंगलम बेसिन में गाद (सेडिमेंट) दर के आकलन और गाद परिवहन हेतु भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाओं के संबंध में दो बोलीदाताओं से आरएफपी प्राप्त हुआ है. आरएफपी की तकनीकी बोली की मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है.

भारत की बारहमासी नदियों हेतु ऐक्वेटिक हैबिटेट एटलस

सभी मछली प्रजातियों, प्लैंकटन और बेन्थिक इन्वर्टीब्रेट, अन्य मैक्रो-फ्लोरा की जानकारी/डाटा को संकलित करने, बारहमासी नदी प्रणाली में चिन्हित किए गए नदियों की पहुँच में वर्षों तक अपने वातावरण के आधार पर अस्तित्व मे रहने वाले प्रत्येक अम्ब्रेला प्रजातियों के हैबिटेट का वर्गीकरण करने के लिए के.ज.आ. ने सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआईएफआरआई) के सहयोग से एक ऐक्वेटिक हैबिटेट एटलस तैयार करने का कार्य आरंभ किया है. एटलस भारत में एक नदी बेसिन में पर्यावरणीय प्रवाह का आकलन करने में मदद करेगा. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत के.ज.आ. की परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में वर्ष 2016 में ऐक्वेटिक हैबिटेट एटलस बनाने की मंजूरी दी गई थी.

के.ज.आ. ने कार्यों का मार्गदर्शन और समीक्षा करने के लिए जनवरी-2020 में मुख्य अभियंता(ईएमओ) की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार और समीक्षा समिति (टीएआरसी) का गठन किया, जिसमे के.ज.आ., पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य मत्स्य विभाग, राज्य के वन विभागों, एनआईएच और अन्य प्रमुख संगठनों (नामतः एनडबल्यूआईसी आदि) के अधिकारी शामिल हैं. ऐक्वेटिक हैबिटेट एटलस बनाने का कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 36 महीनों में पूरा किया जाएगा.

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, के.ज.आ., सीआईएफआरआई अधिकारियों के साथ टार्क बैठक की अध्यक्षता करते हुए

इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का ईआईए अध्ययन

वाप्कोस लिमिटेड को सौंपी गई पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने के लिए समिति की 12वीं बैठक मुख्य अभियंता(ईएमओ), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 02.02.2020 को गांधीनगर में आयोजित की गई. इस बैठक में एनडबल्यूडीए, वाप्कोस, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया. इस बैठक में इन लिंक की ईआईए अध्ययन रिपोर्ट के मसौदे के संदर्भ में प्रभावित गांवों, पूर्णा वन्य जीवन अभयारण्य के बहुत छोटे हिस्से के जलमग्न होने, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास पैकेज, फीडर पाइप लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण की गैर-आवश्यकता, डाउनस्ट्रीम प्रवाह की सीमा, परियोजना से प्रभावित जनता (पीएपी) के लिए मानदंड आदि पर चर्चा की गई. रिपोर्ट में विसंगतियों को संशोधित करने के लिए सलाहकार, वाप्कोस को सूचित किया गया.

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, के.ज.आ., इंटरलिंकिंग परियोजनाओं के ईआईए अध्ययन से संबंधित समिति की 12 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए

तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)

तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की चल रही योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था. सीएमआईएस के कार्यान्वयन और निर्माण के लिए के.ज.आ. ने सीएसआईआर-नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा को परियोजना निष्पादक के रूप में कार्य करने के लिए तथा गोवा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों में प्रोजेक्ट फेसिलिटेटर के तौर पर सीएमआईएस का कार्यान्वयन करवाने के लिए उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) का गठन, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में स्थल का निर्धारण, मापदंडों की विशिष्ट सूची, खरीदे जाने वाले उपकरण, परियोजना की प्रगति की समीक्षा, परियोजना की स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो मध्यावधि सुधार के सुझाव आदि के लिए तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए किया गया है.

पीएमसी की पहली बैठक 30.01.2020 को एनआईओ, गोवा में बुलाई गई थी. श्री एम.के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता, केजीबीओ, के.ज.आ., हैदराबाद ने परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) के अध्यक्ष के रूप में सीएमआईएस के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की. पीएमसी सदस्यों ने साइट की स्थापना के लिए उत्तरी गोवा के स्थलों का भी दौरा किया.

श्री एम.के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता, के.ज.आ के नेतृत्व में परियोजना निगरानी समिति द्वारा उत्तरी गोवा में स्थल का दौरा

के.ज.आ. की टीम का कोपिली जल विद्युत परियोजना का दौरा

कोपिली जलविद्युत परियोजना 275 मेगावाट की एक जलविद्युत परियोजना है जो असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में स्थित है. यह परियोजना नॉर्थ इलेक्ट्रिक पावर को-ऑपरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित और प्रचालित है. दिनांक 07.10.2019 को एक दुर्घटना हुई, जिसमें पेनस्टॉक टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप कोपिली पावर हाउस में जल भराव हो गया. जल भराव के कारण बिजली घर मलबे से भर गया. इस घटना की जांच के लिए सदस्य(हाइड्रो), सीईए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. श्री टी.के. शिवराजन, मुख्य अभियंता, के.ज.आ. जो समिति के एक सदस्य हैं, ने 23 से 25 जनवरी 2020 के दौरान स्थल का दौरा किया ताकि पेनस्टाक के टूटने के कारण का पता लगाया जा सके और इसकी शीघ्र बहाली के लिए उपचारात्मक उपाय किये जा सकें.

टूटा हुआ पेनस्टॉक

राजस्थान में चंबल बेसिन बांधों के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों का दौरा

के.ज.आ. के अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के विभिन्न बांध सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान करने के अनुरोध के आधार पर 7 से 8 जनवरी, 2020 के दौरान 3 बांधों - राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज राजस्थान का निरीक्षण किया. ये बांध जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आगामी डीआरआईपी चरण- II में प्रस्तावित किए गए हैं.

नॉर्थ कोयल परियोजना की समीक्षा

झारखंड और बिहार राज्य में नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 17.01.2020 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एक बैठक ली गई. परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति की स्थिति, उत्तर कोयल परियोजना की 7वीं संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के लिए कैबिनेट की मंजूरी, पुनःस्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) पैकेज तथा श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई. माननीय मंत्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने पर जोर दिया. इस बैठक में माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय ,सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ., संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., आयुक्त(एफएम), ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., मुख्य अभियंता(आईएमओ), के.ज.आ., मुख्य अभियंता(अभिकल्प), के.ज.आ. और सीएमडी, मेसर्स वाप्कोस लिमिटेड ने भाग लिया.

नॉर्थ कोयल परियोजना के अंतर्गत मंडल बांध

त्रिपुरा की परियोजनाओं के लिए पीएफआर

20 जून 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार हौरा बांध और चंपई चैरा बांध परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा डीपीआर बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग (डब्ल्यूआर), त्रिपुरा सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग को डिपाजिट कार्य के तौर पर सौंपा गया. निधि की पहली किस्त त्रिपुरा सरकार द्वारा के.ज.आ. को 7 जुलाई 2019 को जारी की जा सकी. यह याद रखना उचित होगा कि हौरा डैम परियोजना और चंपई चैरा डैम के लिए जो व्यवहार्यता अध्ययन पहले के.ज.आ. द्वारा किया गया था वह एक अलग विपथन स्थल के लिए था और त्रिपुरा सरकार को क्रमशः सितंबर 1995 और अक्टूबर 1993 में प्रस्तुत किया गया था. समय बीतने के साथ-साथ, क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव आया है और इसलिए परियोजना के प्रस्ताव पर फिर विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है.

इन दोनों परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और 31 दिसंबर 2019 को लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार के प्रधान सचिव को सौंप दी गई है. दोनों परियोजनाएं सिंचाई योजना हैं, जिसमें बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, औद्योगिक जल एवं मछली पालन, पशुपालन, संचार, पर्यटन आदि से जुड़े अन्य लाभ हैं.

कार्यकारी अभियंता, एनईआईडी- I, सिलचर त्रिपुरा में परियोजनाओं के पीएफआर का सौंपते हुए

परियोजना	नदी	सीसीए (हे.)	सिंचाई तीव्रता	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
हौरा बांध परियोजना	हौरा	700	200%	50.82
चंपई चैरा बांध परियोजना	चंपई चैरा	700	200%	46.44

बाढ़ प्रबंधन पर हिंदी तकनीकी संगोष्ठी

राजभाषा हिंदी में "भारत में बाढ़ प्रबंधन" विषय पर दूसरा तकनीकी सम्मेलन महानदी और पूर्वी नदी संगठन, के.ज.आ., भुवनेश्वर द्वारा हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली की ओर से नाल्को नगर, भुवनेश्वर में 20.01.2020 को आयोजित किया गया. इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ., नई दिल्ली द्वारा श्री अंबरीश नायक, मुख्य अभियंता, एमईआरओ, के.ज.आ., भुवनेश्वर, श्री आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता, एनबीओ, भोपाल, श्री मोतीलाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ, नई दिल्ली और श्रीमती राजिन्दर पाल, उप निदेशक, के.ज.आ, नई दिल्ली की उपस्थिति में की गई. सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन और श्री मोतीलाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली के स्वागत भाषण से हुआ तथा इसके बाद श्री अंबरीश नायक, मु.अ., एमईआरओ, के.ज.आ, भुवनेश्वर, श्री आदित्य शर्मा, मु.अ., एनबीओ, भोपाल और श्रीमती राजिन्दर पाल, उप-निदेशक, के.ज.आ, नई दिल्ली ने भी भाषण दिए.

सम्मेलन में हिंदी के दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए. के.ज.आ., सीजीडब्लूबी, एनडब्लूडीए, वाप्कोस, एनएचएआई और जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार के लगभग 150 अधिकारीगण इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे.

श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी) भारत में बाढ़ प्रबंधन पर हिंदी तकनीकी संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

सीपीएमयू ने 10 जनवरी 2020 को गांधी हिलॉक के बाएं किनारे पर अतिरिक्त उत्प्लाव (स्पिलवे) के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा के लिए विश्व बैंक की टीम के साथ हीराकुंड बांध का दौरा किया. इस टीम द्वारा पुनःस्थापन और पुनर्वास कार्यों पर बांध अधिकारियों द्वारा की गई प्रगति की भी समीक्षा की गई. डीआरआईपी के लंबित मुद्दों और आगामी डीआरआईपी चरण II व चरण III की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 10 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव, जल संसाधन के साथ विश्व बैंक और सीपीएमयू टीम की एक आधिकारिक बैठक हुई.

उत्तम बांध सुरक्षा प्रथाओं का प्रसार करने के लिए, दुनिया भर में उपलब्ध विशेषज्ञता को संग्रहित करके बांध सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं. "भूकंपीय खतरे का मूल्यांकन और बांध की भूवैज्ञानिक परिस्थितियां" और "बांध के हजार्ड पोटैन्श्यल को वर्गीकृत करने के लिए दिशानिर्देश" के मसौदे पर दो समीक्षा बैठकें आयोजित हुईं.

श्री नित्यानंद राय, निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण), सुश्री चेतना, उप निदेशक, जल विज्ञान (मध्य) और सुश्री पायल गोयल, सहायक निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) ने डीआरआईपी - चरण -II के अंतर्गत 20.01.2020 से 22.01.2020 तक प्रशिक्षण के दौरान रांची, झारखंड में डिजाईन बाढ़ विश्लेषण पर जल संसाधन विभाग , झारखंड सरकार के अधिकारियों को व्याख्यान दिए.

बांधों के रैपिड रिस्क स्क्रीनिंग के फ्रेमवर्क के विकास के लिए दूसरी कार्यशाला 20 से 31 जनवरी, 2020 के दौरान के.ज.आ, नई दिल्ली में आयोजित की गई. विश्व बैंक के जोखिम विशेषज्ञों, के.ज.आ. के अधिकारियों और 6 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक समर्पित टीम ने विभिन्न मानदंडों पर विचार-विमर्श किया, ताकि डिजाइन मानदंडों, मौजूदा परिस्थितियों, सुरक्षा प्रोटोकॉल आदि के आधार पर भारतीय बांधों की स्क्रीनिंग की जा सके. जोखिम आधारित निर्णय प्रणाली का यह प्रयास बांधों के लिए संसाधन आवंटन की प्राथमिकता तय करने में लाभकारी होगा.

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित डीआरआईपी और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएच पी) के तत्वावधान में केरल जल संसाधन विभाग द्वारा 23 से 24 जनवरी 2020 में तिरुवनंतपुरम में "बाढ़ प्रबंधन के लिए नीतियां और रणनीतियाँ: केरल परिदृश्य" (केरल फ्लडकॉन 2020) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का उद्घाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता माननीय जल संसाधन मंत्री, केरल सरकार द्वारा की गई. अतिरिक्त सचिव (ज.सं न.वि एवं गं.सं.वि.) भी इस सम्मलेन में उपस्थित रहीं. विश्व बैंक, एनएचपी और डी आरआईपी के अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया. श्री प्रमोद नारायण, परियोजना निदेशक, डीआरआईपी द्वारा प्लीनरी सत्र के दौरान "बाढ़ जोखिम प्रबंधन में बांधों की भूमिका" विषय पर एक प्रस्तुति दी गई.

सिंचाई प्रणाली की बेंचमार्किंग पर कोर ग्रुप की 10वीं बैठक

भारत में सिंचाई प्रणाली की बेंचमार्किंग पर कोर ग्रुप की दसवीं बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. एवं कोर ग्रुप के अध्यक्ष की अध्यक्षता में के.ज.आ., नई दिल्ली में 23.01.2020 को आयोजित हुई. इस बैठक के दौरान, उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के बेंचमार्किंग के लक्ष्य पर प्रकाश डाला, जो सिस्टम डिलीवरी और समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है.

बैठक में 17 राज्यों जो पहले ही अपने राज्य स्तरीय कोर ग्रुप का गठन कर चुके हैं, उनमें राज्य स्तरीय कोर समूह (एसएलसीजी) के गठन के संबंध में राज्यों की प्रगति और कम से कम 5 परियोजनाओं के लिए की गई बेंचमार्किंग अध्ययन (9वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार) की समीक्षा तथा चर्चा की गई. तदनुसार, बिहार में वाल्मी पटना के प्रतिनिधि ने बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के बेंचमार्किंग का विवरण प्रस्तुत किया, नामतः

- सोन नहर प्रणाली (पटना मुख्य नहर और आरा मुख्य नहर)
- कुदरा वीयर योजना
- कमला वीयर योजना
- फुलवरिया जलाशय योजना
- चंदन जलाशय योजना

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने भी तमिलनाडु में 4 सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग से संबंधित कार्य पर एक प्रस्तुति दी.

श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्लूपीएंडपी) बेंचमार्किंग मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए

इस कोर ग्रुप द्वारा 17 राज्यों जो पहले ही एसएलसीजी का गठन कर चुके हैं नामतः मेघालय, गुजरात, उड़ीसा, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु और नागालैंड की बेंचमार्किंग गतिविधियों पर प्रगति की राज्यवार समीक्षा की गई. अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने एसएलसीजी का गठन करें और अपने एसएलसीजी बनाने के लिए कम से कम 5 परियोजनाओं की बेंचमार्किंग अध्ययन को पूरा करें.

बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह

भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह (जेजीई) गठित किया गया था ताकि भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के निकटवर्ती मैदानों में बारम्बार आने वाली बाढ़ तथा होने वाले कटाव के संभावित कारणों एवं प्रभावों के बारे में चर्चा करने और उनका आकलन करने के लिए दोनों सरकारों को उपयुक्त और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य उपचारात्मक उपायों की सलाह दी जा सके. भूटान में पहली बैठक 1 से 5 नवंबर 2004 के दौरान आयोजित की गई थी. इस बैठक के दौरान, जेजीई ने कई चर्चाएं की और फुएंटशोलिंग, गोम्टू, पुगली और बूक्सा डुआर के आसपास भारत-भूटान सीमा क्षेत्रों में कई स्थलों का दौरा किया. जेजीई की पिछली बैठक अर्थात 9वीं बैठक पुनाखा, भूटान में 7 से 8 जनवरी 2020 के दौरान आयोजित की गई. जेजीई की इस 9वीं बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1. दोनों देशों के बीच मित्रता, आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करना.

2. नवंबर 2018 में गुवाहाटी में हुई 8वीं जेजीई बैठक के निर्णय पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा.

- 1 : 50000 के पैमाने पर भारत और भूटान की साझी नदी प्रणाली को दिखाने वाले मानचित्रों का संकलन और एकीकरण
- धनसिरी, पुथिमारी और मानस नदियों का तलछट भार विश्लेषण
- भूस्खलन और बाढ़ के कारणों पर की गई कार्रवाई और भवानीजोरा के लिए उपचारात्मक उपायों की स्थिति
- खरबंदी चेक पोस्ट, रिंनचेन्डिंगगोएनपा और झारना स्लाइड हेतु स्थिरता मूल्यांकन के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों की समीक्षा

3. अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 1 किमी अनुप्रवाह में तोर्सा नदी के बाएं किनारे पर भारत में छोटा जयगांव क्षेत्र में कटाव की समीक्षा की गई. जैसा कि भूटान की शाही

सरकार द्वारा सूचित किया गया कि भूटान में भूमि सुधार कार्य पहले से ही प्रस्तावित हैं और जेजीई ने संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी), भूटान की शाही सरकार को संदर्भ के लिए जेटीटी के साथ भूटान में प्रस्तावित भूमि सुधार कार्य परियोजना के प्रासंगिक विवरण को साझा करने के लिए निर्देश दिया.

4. भारत सरकार ने बैठक में दो नए एजेंडा आइटम को शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया, नामतः (क) भारत और भूटान की साझी नदियों से संबंधित बाढ़ संबंधी गतिविधियों के लिए फुएंटशोलिंग,भूटान में भूटान इन्वेस्टीगेशन डिवीजन (बीआईडी), के.ज.आ. की भागीदारी और (ख) भूटान में प्रस्तावित संकोश जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित कार्य. हालांकि, भूटानी पक्ष ने इन नए एजेंडा आइटम को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पूर्व परामर्श की आवश्यकता है. भारतीय पक्ष ने अगली जेजीई बैठक में विचार-विमर्श के लिए इन एजेंडा आइटम को शामिल करने का अनुरोध किया.

5. अगली जेजीई की बैठक दीघा, पश्चिम बंगाल में या तो 2020 की अंतिम तिमाही अथवा 2021 की पहली तिमाही में होगी.

जलाशय प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों की वर्तमान भंडारण स्थिति की देखरेख करता है और हर ब्रहस्पतिवार को इसका एक बुलेटिन जारी करता है. इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.091 घन किमी है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 घन किमी की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 % है. जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.01.2020 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध वर्तमान भंडारण 119.434 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल वर्तमान धारण क्षमता का 70% है. यह पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान की वर्तमान भंडारण का 156% है और पिछले10 वर्ष में औसत भंडारण का 144% है.

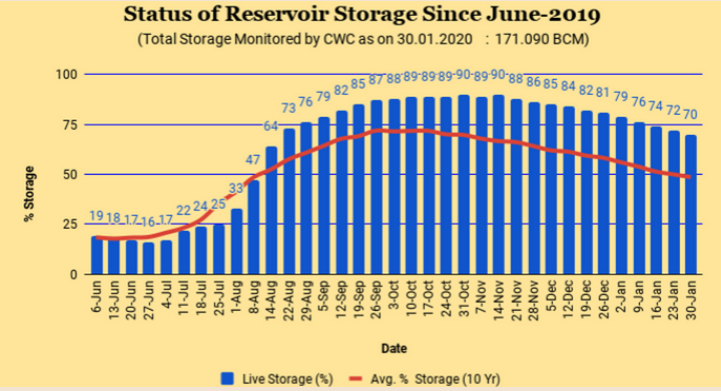

भारत दर्शन

केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा अधिकारियों के 31वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) के लिए भारत दर्शन घटक (2 सप्ताह) 25.01.2020 को शुरू हुआ. इस समूह में कुल 44 प्रशिक्षु अधिकारी थे, जिनमें से 43 ईएसई 2018 के माध्यम से भर्ती किए गए और एक पिछले ईएसई से. भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का दौरा पहले सप्ताह में किया गया और दक्षिणी भाग का दौरा फरवरी 2020 के अगले सप्ताह में किया जाना था. प्रशिक्षु अधिकारियों ने 25.01.2020 को नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) का दौरा किया. आईएसपी की आधारशिला अक्टूबर-1984 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उनकी हत्या के एक सप्ताह पहले रखी गई थी. आईएसपी की भंडारण क्षमता देश में सबसे बड़ी है. इसके बाद प्रशिक्षु अधिकारियों को ओंमकारेश्वर परियोजना (ओएसपी), नर्मदा मुख्य नहर का साइफन जो साबरमती नदी पर है, साबरमती रिवर फ्रंट, सरदार सरोवर परियोजना और इसका कमान क्षेत्र तथा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वगैरह का दौरा करवाया गया.

जल क्षेत्र-समाचार

- महादयी नदी से कुछ मात्रा में पानी को मोड़ा गया (राष्ट्रीय सहारा, 02.01.2020)
- तालाब होंगे जिंदा तो बढ़ेगा भूजल स्तर (नवभारत टाईम्स, 04.01.2020))
- ग्लेशियर पिघलने से हिमालय की झीलों में बाढ़ का खतरा (राजस्थान पत्रिका, 05.01.2020)
- गंगा में गिरा गंदा पानी तो तत्काल बंद होंगे उद्योग (राष्ट्रीय सहारा, 07.01.2020)
- गंगा—ब्रह्मपुत्र—मेघना डेल्टा में 1.4 मी. बढ़ेगा जलस्तर (अमर उजाला, 08.01.2020)
- गंगा के उद्धार का संगम बनेंगे यूपी के कई जिले (राजस्थान पत्रिका, 09.01.2020)
- बिना किसी केमिकल के पानी की हर बूंद का हो रहा संरक्षण (दैनिक जागरण, 20.01.2020)
- खान—शिप्रा से कलियासोत तक 33 नदी का दो साल में होगा शुद्धीकरण (राजस्थान पत्रिका, 21.01.2020)
- भूजल संकट की गंभीरता (जागरण, 21.01.2020)
- रेगिस्तान में जल भण्डार, वो भी 4800 खरब लीटर (राजस्थान पत्रिका, 22.01.2020)
- प्यासे रेगिस्तान में हिलोरे मार रहे हैं तेल—गैस—पानी के समंदर (राजस्थान पत्रिका, 23.01.2020)
- एसवाईएल पर पंजाब का नया पैंतरा — प्रस्तावित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एक्ट में संशोधन की मांग (पंजाब केसरी, 24.01.2020)

गणतंत्र दिवस समारोह

स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति

डॉ. राकेश कुमार गुप्ता ने अध्यक्ष, केआरएमबी, हैदराबाद से सदस्य (डीएंडआर),के.ज.आ. का पदभार गृहण किया

श्री भोपाल सिंह ने दिनांक 27.01.2020 को महानिदेशक, एनडब्लूडीए का कार्यभार गृहण किया

पदोन्नति (के.ज.अ.से.)

6 अधिकारी-जेएजी से एसएजी
6 अधिकारी-एसटीएस से जेएजी
39 अधिकारी-जेटीएस से एसटीएस

के.ज.आ के अधिकारियों का स्वागत (ईएसई -2016/17)

के.ज.आ. के अधिकारियों की जरूरतों और उनके कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने हेतु कार्यकलापों के विस्तृत विस्तार के साथ के.ज.आ. की विदाई समिति को पुनर्गठित किया गया और उसका नाम बदलकर सीडब्ल्यूईएस वेलफेयर कमेटी कर दिया गया है. सीडब्ल्यूईएस वेलफेयर कमेटी का पहला कार्यक्रम सीडब्ल्यूईएस बन्धुत्व के लिए एक मिलन समारोह था जिसे 2020 में नए साल / मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2020 को ऑडिटोरियम, के ज.आ., न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग, आर के पुरम, नई दिल्ली में ईएसई 2016 और 2017 बैच के नए भर्ती अधिकारियों के लिए एक परिचयात्मक स्वागत के साथ मनाया गया. अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य, डब्लूपीएंडपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने ईएसई 2016 और 2017 बैच के नए शामिल किए गए सीडब्ल्यूईएस अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया. उन्होंने सीडब्ल्यूईएस में अपने अनुभवों को साझा किया और अभिप्रेरित करते हुए उन्हें उज्ज्वल कैरियर की शुभकामनाएँ दी. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें सीडब्ल्यूईएस अधिकारियों ने कुछ शानदार वाद्य और गायन और साथ-साथ युवा सीडब्ल्यूईएस अधिकारियों ने अभिनय/मेम की प्रस्तुतियां दीं.

इतिहास से- भाखड़ा की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें

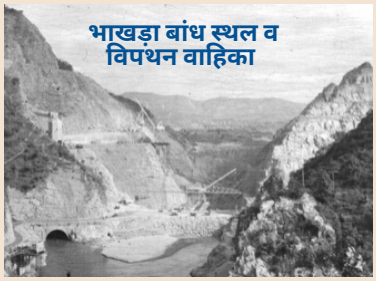
भाखड़ा बांध स्थल व विपथन वाहिका

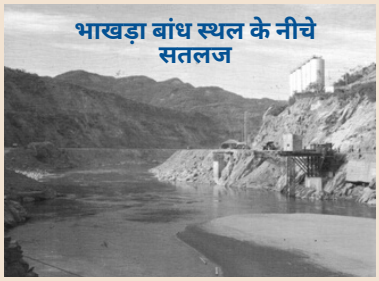
भाखड़ा बांध स्थल के नीचे सतलज

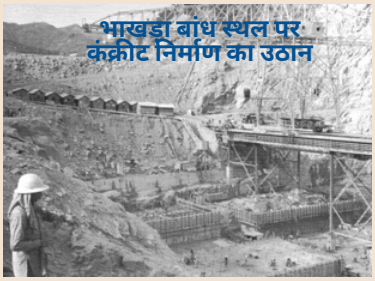
भाखड़ा बांध स्थल पर कंक्रीट निर्माण का उठान

बांध निर्माण में यंत्रीकृत कंक्रीटिंकरण

भाखड़ा बांध कार्यों के लिए तैयार पुल और किनारें

नांगल बांध के ऊपर सड़क और हेड वर्क्स

नांगल बांध

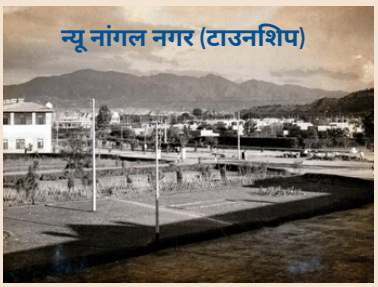
न्यू नांगल नगर (टाउनशिप)

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा०स०प्र०)-मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ई०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (पी०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री एच एस सेंगर , निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस के राजन, निदेशक (तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक (डबल्यू०पी०&पी० समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक (आई०एस०एम०-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक (डी०एंडआर०समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य सचिव

अनुवादः श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (डब्ल्यू०एस०ई०), के०ज०आ०, नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in